

गहलोत सरकार के जाने के ग्यारह महीने बाद अभी भी उस सरकार की बात करने की इतनी उत्कंठा क्यों?

राजेश शर्मा
प्रधान सम्पादक
राष्ट्रदूत

ल गभग साल ६१ र पहले, राष्ट्रदूत ने रॉ के पुराने चीफ, ए.एस. दुलत साहब की नई किताब "लाइफ इन द

शेडोज़" पर एक "बुक इवेंट" (पुस्तक पर गहन चर्चा) आयोजित किया था। दुलत साहब राजस्थान कैडर के आई.पी.एस. अफसर थे, पर अधिकतर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की विभिन्न एजेंसियों, जैसे आई.बी., रॉ आदि में "पोस्टेड" रहे, अतः उनके लिए आयोजित "इवेंट" काफी रोचक व "पापुलर" रहा, विशेषकर, राजस्थान पुलिस उच्चाधिकारियों में। "वर्ड ऑफ़ माउथ" से इवेंट दिल्ली के "इन्स्टीट्यूट ऑफ़ सॉल्यूटिव" में भी काफी चर्चित रहा। दिल्ली के जिमखाना क्लब में मेरी जब भी "इन्स्टीट्यूट ऑफ़िसरों" से मुलाकात व चर्चा हुई, तो उनके सभी पुराने साथियों ने "दुलत साहब" की किताब को "हाइ लाइट" करने को सतही तौर पर काफी सराहा पर मुझे महसूस हुआ, कि, इस सर्किल में दुलत साहब की किताब को लेकर थोड़ी सी "अनईजिनेस" (बेचैनी सी) भी है।

रॉ के एक रिटायर्ड वरिष्ठतम अधिकारी से, जिसे कालान्तर में थोड़ा में गहराई से जानने लगा, एक शाम को अपनी इस "अनईजिनेस" के अहसास को मैंने शेयर किया और इस अनईजिनेस का कारण जानने की कोशिश की, क्योंकि "बुक इवेंट" के बाद मैंने दुलत

सरकारी तंत्र, सरकारी प्रशासन "लाइन ऑफ़ कमाण्ड" (आदेशों की शृंखला) के मार्फत काम करता है। जिला स्तर पर, उदाहरण के लिए पुलिस तंत्र में एस.पी., एडिशनल एस.पी., थानाधिकारी आदि की शृंखला होती है। गहलोत ने विधायक को प्रशासन की धुरी बनाकर यह "लाइन ऑफ़ कमाण्ड" तोड़ दिया था और, सभी स्तर के कर्मचारी केवल विधायक की ओर देखने लगे अगले आदेश की प्रतीक्षा में। वरिष्ठता केवल "अलंकार" बनकर रह गयी, उसका प्रशासनिक महत्व लगभग खत्म हो गया। इस प्रशासनिक अराजकता से बचने के लिए, पुराने मुख्यमंत्री, कम से कम भैरोंसिंह शेखावत तक, विधायकों की, अफसर की ट्रांसफर-पोस्टिंग की मांग पर दो टूक जवाब देते थे, "तुम्हारे कहने पर अफसर तो हटा देता हूँ, पर उसकी जगह किसे लगाऊँ यह मैं ही निर्णय लूंगा।" मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार विधायक को ही दे दिया था, इससे प्रशासनिक अराजकता तो फैलनी ही थी। पुराने मुख्यमंत्रियों ने तो प्रशासनिक अराजकता को फैलने से रोकने के लिए कुछ नीतियां-रीतियां बनाईं, लेकिन, गहलोत ने इस अराजकता को सींचने के लिए, पनपाने के लिए, बांध के सब गेट खोल दिये थे। नारा था, प्रशासनिक अराजकता जाए भाड़ में, लेकिन, मेरी सलतनत सुरक्षित बनी रहे। सरकारी व प्रशासनिक संस्थानों की तोड़-मरोड़ की गूँज ग्यारह महीने बाद भी सुनी जा सकती है। और भ्रष्टाचार के इस पहिए को थमने और पलटने में ना जाने कितने वर्ष लगेंगे।

रॉ के पूर्व चीफ़ दुलत साहब की किताब पर पुलिस के उच्चतम क्षेत्र में "अनईजिनेस" थी, कि उन्होंने वो सब लिख दिया जो लोगों को मालूम तो था पर विश्वसनीयता संदिग्ध थी। किताब ने सब बातों को सत्यापित कर दिया। यही बात "करप्शन" को लेकर है। सब जानते थे कि थोड़ा करप्शन तो होता ही है, पर गहलोत ने विधायक को कॉन्स्टिट्यूएण्टी का मुख्यमंत्री बताकर करप्शन को सरकारी मान्यता दे दी। करप्शन इतना बेधड़क, खुल्लम-खुला होने लगा कि सचिवालय में सरकारी अलमारी में "रिश्वत" का सोना व रुपये पकड़े गये, पर जाँच की औपचारिकता ही पूरी हुई।

देकर, कि स्थानीय विधायक ही अपनी "कॉन्स्टिट्यूएण्टी" (चुनाव क्षेत्र) का मुख्यमंत्री है। उसकी ही चलेगी, और सरकारी मशीनरी उस को समर्थन/सहयोग दे। इस नई व्यवस्था में सरकारी "इन्स्टीट्यूशन", (प्रशासन) की परम्पराएं शून्य, प्रभावहीन तो होनी ही थीं और यहीं से खाओ और खाने दो की ही नहीं, बल्कि खाना जायज़ है, की

एक उदाहरण जयपुर के नज़दीक कोटपूतली कस्बे का है। वहाँ "तथाकथित" सरकारी मापदण्ड के अनुसार रोड चौड़ी करने के लिए 150 घरों व दुकानों में भारी तोड़फोड़ की गई। कड़ियों के पास खेतड़ी राज्य के पट्टे मौजूद थे, अन्य के पास नगर पालिका द्वारा स्वीकृत नक्शे थे। पर स्थानीय प्रशासन के लिये विधायक क्षेत्र का "घोषित मुख्यमंत्री" था। पीड़ित जनता ने न्यायालय से भी आदेश प्राप्त किये, पर न्यायालय के आदेश भी तो अंततोगत्वा प्रशासन ही लागू करता है।

व्यवस्था बैठाई गई। यह सिस्टम कैसे बना इसकी डीटेल चर्चा आगे करेंगे, किंतु "करप्शन" इतना, बेधड़क, खुल्लम-खुल्ला होने लगा, कि सचिवालय में सरकारी अलमारी में "रिश्वत" का सोना व रुपये पकड़े गये, पर जाँच की औपचारिकता ही पूरी की गई। "नेट

सन् 1989 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जोधपुर वासी जिस भी काम के लिए कहते, उनका जवाब होता था, "यह स्थानीय मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बताओ" तंग आकर एक आदमी ने हजार रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, "दिल्ली के चांदनी चौक में बाबा छाप जर्द का तम्बाकू मिलता है, अगली बार दिल्ली से आये तो दो डिब्बे लेते आइयेगा।"

रिजल्ट", यह विश्वास बन गया, कि इसी व्यवस्था का हिस्सा बनने अन्याय कर्मचारी का भविष्य नहीं है। प्रशासनिक "इन्स्टीट्यूशन" को इतना दीमक लगा कि अब शायद कई दशक लगेंगे, करप्शन को "परमिसेबल लिमिटेड" में लाने के लिए। यह "परमानेंट देन" है गहलोत के प्रशासन की। और, यह "गिफ्ट" गहलोत बार-बार देना चाहेंगे। क्योंकि उनके मन में कहीं भी कुछ रूढ़िवादी नहीं आती कि, उन्होंने राज्य में प्रजातंत्र की जड़ें उखाड़ कर फेंक दी हैं। वे मन से विश्वास करते हैं, कि राजा ही तो राज्य है, अतः किसी भी तरह, राजा को बनाये रखना, सुरक्षित रखना ही "राजधर्म" है। उनके मन में शायद एक ही अफसोस है, कि पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन पाये। वे इसके लिए, रणनीति के क्रियान्वन में कमी को ही हार का कारण मानते हैं। "करप्शन" को राज धर्म बनाने के मूल सिद्धांत को कड़ा बुरा नहीं मानते।

पर, इस विवरण के बाद में भी यह प्रश्न अनुत्तरित सा ही रह गया है, कि अब इस समय उनकी सरकार के जाने के ग्यारह महीने बाद भी निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में बात करने की उत्कण्ठा क्यों है? इस संदर्भ में रामायण का वह प्रसंग स्मरण हो आता है, जब युद्ध के दौरान राम के बाणों की बारिश से घायल होकर रावण मूर्छित हो गया था और उनके सारथी ने उनके रथ को लंका में ले जाने के लिए मोड़ा था, उस समय लक्ष्मण, घायल लंका को खत्म करने के लिए तत्पर और तैयार थे। राम ने लक्ष्मण को रोका और कहा, रावण कोई साधारण शत्रु नहीं है, जिसे जैसे-तैसे भागते हुए घायल तथा मूर्छित अवस्था में मार कर, विजय हासिल करना पर्याप्त है। इसी संदर्भ में राम ने आगे कहा कि यह युद्ध धर्म को स्थापित करने के लिए लड़ा गया है, राज्य पाने के लिए नहीं। रावण अधर्म का प्रतीक है, उसे सबके सामने युद्ध करके और पराजित करके मारना जरूरी



गहलोत के मन में कहीं भी कुछ रूढ़िवादी नहीं आती कि उन्होंने राज्य में प्रजातंत्र की जड़ें उखाड़कर फेंक दीं। वे मन से विश्वास करते हैं कि राजा को बनाये रखना ही राजधर्म है। करप्शन को राजधर्म बनाने के मूल सिद्धांत को वे कतई बुरा नहीं मानते। उनकी सरकार जाने के ग्यारह माह बाद गहलोत के बारे में बात करने की उत्कंठा क्यों है? इस संदर्भ में रामायण का प्रसंग याद आता है। जब मूर्छित रावण को उमाका साथी लंका वापस ले जा रहा था, लक्ष्मण घायल रावण को खत्म करने के लिए तत्पर थे। राम ने उन्हें रोका और कहा कि रावण को सबके सामने युद्ध में पराजित करके मारना जरूरी है, ताकि यह साबित हो जाए कि अधर्म के रास्ते चल कर, फरेब से, छल से चाहे कोई सोने की लंका बना ले, उसका अन्त अशुभ व विध्वंसकारी होता है।

है। जिससे यह सदा के लिये साबित हो जाये कि अधर्म के रास्ते पर चलकर फरेब से, छल से, चाहे कोई सोने की लंका तो बना ले, पर इसका अन्त अशुभ और विध्वंसकारी ही होता है। राम के कहने का आशय था कि रावण कोई चिन्दी चोर नहीं था, जिसे रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दण्ड देना पर्याप्त है।

किसी भी मायने में गहलोत भी कोई चिन्दी चोर नहीं थे। अतः उन्हें भी चुनाव में हरा देना काफी नहीं है। उनकी हार पर चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि, कई मायनों में तो वह "युग पुरुष" थे, जिसने सरकार की, प्रशासन की परिभाषा ही बदल दी, अपने कार्यकाल में अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी को "इन्स्टीट्यूशनलाइज्ड" कर दिया। यानी सरकारी सिस्टम का "जायज़" हिस्सा बना दिया, यह नारा देकर कि विधायक ही अपने क्षेत्र का मुख्यमंत्री है।

अनंद द ग्राउण्ड यह प्रतिनिधित्व हुआ, और उसका एक मूल उदाहरण जयपुर के नज़दीक कस्बा-ए-कोटपुतली में देखने को मिला। जहाँ नेशनल हाईवे से जुड़ी रोड को "तथाकथित" सरकारी मापदण्ड के अनुसार चौड़ा करने और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए लगभग 150 घरों और दुकानों की भारी तोड़-फोड़ की गई। कड़ियों के पास खेतड़ी राज्य के पट्टे मौजूद थे, अन्य के पास निगम द्वारा स्वीकृत व पास किये गये नक्शे थे। पर, न्याय के लिए कहीं गुहार की जाये, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के लिए तो विधायक उस क्षेत्र का "घोषित मुख्यमंत्री" था। पीड़ित जनता ने न्यायालय से आदेश प्राप्त किये पर जनता यह भूल गई कि न्यायालय के आदेश भी अंततोगत्वा प्रशासन ही लागू करता है।

गहलोत के राज के जाने की वजह उनकी सोच, "फिलॉसफी" का सुनियोजित, सटीक क्रियान्वन था। अभाव था या कमी थी तो नैतिक मूल्यों की, स्वस्थ प्रजातंत्रीय फिलॉसफी की,

जिसमें शासन की धुरी होती है जनता, न कि राजा, क्योंकि, राजा की बेलगाम महत्वाकांक्षा का खामियाजा जनता उठाती है और जनता में आक्रोश फैलता है, और इसी आक्रोश की वजह से गहलोत की हार हुई, उनकी सत्ता गई।

गहलोत जन आक्रोश की आंठी के कारण हार गये, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि जनता गहलोत द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली को जाने व पहचाने जिसने हमारे प्रजातंत्र को इतना विकृत बनाया।

रावण की भाँति, केवल गहलोत को हराना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि हार-जीत तो राजनीति का अंग है। गहलोत की हार उस "फिलॉसफी" की हार है, जिसमें जनता केवल एक आंकड़ा होती है, और वो ही जीतता है, जो आंकड़ों की गणित का सही "कॉम्बिनेशन" (संतुलन) बिठा लेता है। गहलोत की इस "फिलॉसफी" की अपूर्णता पर चर्चा करना और असार्थकता बताना जरूरी है। यह ही उस उत्कण्ठा के मूल में है, कि गहलोत के सत्ताच्युत होने के ग्यारह महीने बाद भी गहलोत के बारे में बात करने के लिए बेचैनी रहती है, क्योंकि गहलोत शासन प्रणाली की "फिलॉसफी" की दुर्बलता, निर्वलता और कुरुपता को समझे और समझाये बिना गहलोत को केवल चुनाव में हरा देना वैसा ही है, जैसे कि घायल मूर्छित रावण को रात के अंधेरे में मार देना, जिसे राम ने वर्जित किया था। उस वध में, राजा की मृत्यु से जिनत अवसाद में, रोने-धोने

पुरानी लोकोक्ति थी, "बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है", पर गहलोत ने तो हर डाल पर चुन-चुन कर हर स्तर पर "उल्लू" बिठा दिया, और साथ में "फ्रीडम" दे दी कि "कमाओ और खाओ" का सिद्धान्त पूर्णतया स्वीकार्य है।

में, उस समय की मान्यता व सभ्य समाज के तौर तरीकों से परिभाषित अधर्म, पाप-फरेब आदि की अवांछनीयता दब जाती, उभर कर सामने नहीं आती और राम के वनवास का अधोषित उद्देश्य अपूर्ण रहता।

गहलोत जन आक्रोश की आंठी के कारण हार गये, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि जनता गहलोत द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली को जाने व पहचाने, जिसने हमारे प्रजातंत्र को इतना विकृत बनाया। इतना भयावह व डरावना बनाया।

जिस बेशर्मा से, निर्दयता से, भ्रष्टाचार पनपाया गया, इतनी बेशर्मा, क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। जायज़-नाजायज़ काम की कुंजी पैसा हो गयी। सरकारी महकमे "कलैक्शन केन्द्र" बन गये और हर सक्षम अधिकारी व जनप्रतिनिधि "कलैक्शन एजेंट"। पुरानी लोकोक्ति थी, "बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है", पर गहलोत ने तो हर डाल पर चुन-चुन कर हर स्तर पर "उल्लू" बिठा दिया, और साथ में "फ्रीडम" दे दी कि "कमाओ और खाओ" का सिद्धान्त पूर्णतया स्वीकार्य है। उर, इस बात का है, कि हर स्तर पर "उल्लूओं" को खून मुंह लग गया है, पांच साल में। अब यह "सिस्टम" ठीक होने में कई दशक लगेंगे, और जनता ही इसे ठीक कर सकती है, "बुद्धिमानी" का भाषण नहीं। मन में उत्कण्ठा गहलोत के बारे में बात करने की इसलिए रहती है कि, जनता पूरी तरह समझ ले कि "सिस्टम" को क्या हानि हुई। क्योंकि गहलोत के सोच व कार्य प्रणाली का एक और अनुभव शायद राजस्थान का प्रजातंत्र नहीं झेल पायेगा।

सन् 1989 की बात है, अशोक गहलोत जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उनके आग्रह पर मैं चुनाव कवर करने जोधपुर गया था।

गहलोत के तीसरे कार्यकाल में, भ्रष्टाचार की चरम सीमा की पृष्ठभूमि में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक कार्यरत अफसर ने मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कराते हुए इन हालात के सन्दर्भ में कहा, "आप सरकार से गलत समय लड़ लिये, यह लड़ने का नहीं कमाने का समय था। कोई सा भी प्रोजेक्ट ले जाइये मुख्यमंत्री के पास, प्रोजेक्ट पर चिन्तन, उससे लाभ की चर्चा नहीं होती, केवल यह पूछा जाता है, तुम्हें कितना लाभ होगा और उसमें "हमारी" क्या हिस्सेदारी होगी।"

आर.टी.डी.सी. के होटल घूमर में ठहरा था। अशोक गहलोत का मैसेज आया, जोधपुर के उद्योगपति धेवर चन्द कानूनगो ने शहर के बड़े-बड़े व्यापारियों को नारसे पर बुलाया है, गहलोत भी रहेंगे, आप भी आइये, अच्छी "न्यूज़" मिलेगी। नारसे के बाद कानूनगो ने 150-200 बड़े आमंत्रित

.....इतनी उत्कंठा क्यों?

गहलोत ने अपने कार्यकाल में सरकार और मीडिया के संबंध को भी अपने फायदे अनुसार तोड़ने-मरोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। ज्यादातर स्थानीय मीडिया को विज्ञापनों का प्रलोभन दिया, वहीं अन्य मीडिया को स्पष्ट कह दिया गया कि “हमारी न्यूज छापो, तभी विज्ञापन मिलेंगे।” विरोधात्मक सोच रखने वाले 42 पत्रकारों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। जो मीडिया गहलोत से कृतार्थ थी उसने बेधड़क और बिना सूझ-बूझ के वॉट्सएप पर प्रसारित की जा रही फोन-टैपिंग की रिकॉर्डिंग प्रकाशित की, और जाने अनजाने में स्वयं को भी इस राजनैतिक षड्यंत्र का भागीदार बना लिया। क्योंकि गहलोत के मित्र और पार्टी व्हिप महेश जोशी ने इन प्रकाशनों की बिसात पर ही पायलट व उनके गुट के खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी।

तो आज गहलोत के पदच्युत होने के ग्यारह महीने बाद क्यों गहलोत के व्यक्तित्व पर लिखने की उत्कण्ठा हुई। उत्कण्ठा का कारण था, कि अगर जनता समय से नहीं जागती और गहलोत की शासन प्रणाली को समय की पुकार मानते हुए स्वीकार कर लिया जाता, तो यह स्थापित हो जाता कि जनता तो बेमायने है, हार जीत नारों की विविधता पर निर्भर करती है, नारों के क्रियान्वन पर नहीं।

व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा, अपने अशोक की एक बार फिर एम.पी. का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी ड्यूटी बतती है, कि तन, मन, धन से पूरा सहयोग करें। पर उल्लेखनीय बात यह है, कि इस भारी (तन,मन, धन के) समर्थन के बावजूद गहलोत वह चुनाव हार गये थे, जसवंत सिंह के सामने।

गहलोत यह चुनाव हारेंगे, इसका आभास उस वाक्य से हो गया था, जो जोधपुर में लोग-बाग चटकारे ले ले कर आज भी सुनाया करते हैं। वाक्य के अनुसार, चुनाव व जन समर्थक अभियान के दौरान गहलोत शहर के मोहल्लों व कॉलोनियों में जा रहे थे, जनता के शिकवे, शिकायत सुनने के लिए। एक जगह एकात्रित लोगों ने शिकवे सुनाते हुए कहा, “सड़क बहुत खराब है, चलना मुश्किल हो रहा है।” गहलोत ने जबब में कहा, “यह स्थानीय प्रशासन का मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।” लोगों ने बिजली की कम वोल्टेज और बहुत कम समय के लिए बिजली आने का रोना रोया, तो फिर गहलोत ने बो ही जवाब दिया, “यह तो आर.एस.ई.जी. का काम है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।” किसी ने लॉ एण्ड ऑर्डर, बढ़ती हुई चोरी-चकारी व गुंडागर्दी को शिकायत की, पुनः गहलोत को ओर से जवाब मिला, “यह स्थानीय पुलिस के “डील” करने का मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।” तंग आकर एक आदमी ने हजार रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, “दिल्ली के चंदानी चौक में बाबा छाप जर्द का नम्बूक मिलता है, अगली बार दिल्ली से आयें तो दो डिब्बे लेते आइयेगा।” व्यंग्यात्मक टिप्पणी में जनता

पहला मैसैज यह गया कि, दिल्ली इतनी कमजोर है कि क्षेत्रीय क्षत्रप, मनमर्जी से बिना लगाम राज चला रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि हाई कमान को भी इस भ्रष्टाचार की कमाई से कोई परहेज नहीं है। परंतु गहलोत को लाभ ही लाभ था इस व्यवस्था से। एक तो उनका भ्रष्टाचार “जायज़” हो गया, दूसरा विधायकों की निष्ठा व वफादारी सी प्रतिशत गहलोत के प्रति ही गई और गहलोत ही क्यों मुख्यमंत्री रहें, इसे “जस्टिफाई” करने के लिए (जायज़ उधारने के लिए) एक और तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट “राजद्रोही” हैं और उनके खिलाफ “सैंडिशन” (देशद्रोह) का मुकदमा ठोक दिया गया। “सैंडिशन” के पक्ष में “सबूत” दिये गये कि पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर भाजपा से हाथ मिलाने वाले थे, गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने और कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए।

कहानी पुरानी है तथा इससे सब भली-भांति परिचित हैं, तो आज, गहलोत सरकार गिरने के ग्यारह महीने बाद इस घटनाक्रम की चर्चा क्यों चली है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रजातंत्र बचा है।

प्रेस को रौब से दबाने को, या प्यार से सुलाने की नैसर्गिक फितरत होती है हर सरकार की, बहुत कम प्रशासन इस प्रवृत्ति से बच पाते हैं। इस प्रवृत्ति के बारे में स्वर्गीय उपराष्ट्रपति कृष्ण कान्त ने ऐसे ही प्रकरण के बारे में राज्यसभा में बड़े सटीक ढंग से कहा था, “जब आप खबरों के प्रवाह को जवाब दे रहे हैं, तब आप, अपने तक जानकारीयां पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं।”

गहलोत की राजनीतिक सूझबूझ में कोई कमी नहीं थी, पर इस ज्ञान का वे “सलैक्टिव”, अपनी सुविधा व व्यक्तिगत हित को देखते हुए प्रयोग करते थे और सुविधानुसार, पार्टी का हित, गौण हो जाता था। जब उन्होंने अपने पुत्र को जालौर से टिकट देने का मन बना लिया, उसे राजनीति में स्थापित करने के लिए तो, कलबियों की संख्या का तर्क गौण हो गया। पर जातियां उनके मन के अनुसार गौण या महत्वपूर्ण नहीं हो जातीं, और उनके पुत्र की डेढ़ लाख वोटों से करारी हार हुई।

का नारा दिया नेताओं ने, और धीरे-धीरे अफसरों पर हावी हो गये। तीन बार मुख्यमंत्री रहने के कारण वे सरकारी प्रक्रिया से काफी सुपरिचित हो गये थे। सिस्टम को कैसे और कितना तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, अपने राजनीतिक हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यह खूब समझ गये थे, और किस अफसर को दबाव से, किसको प्रलोभन से, किसको व्यक्तिगत सम्बन्धों से फुसलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और यह भी कि यदि अफसर फिर भी काबू नहीं आता तो, उसे कहाँ और किस टांड पर रखा जा सकता है, उसके रिटायरमेंट तथा दूसरी ओर दिल्ली पर “नियंत्रण” पा लिया, दिल्ली व दिल्ली की “आवश्यकता” की पूर्ति करके।



नतीजा वो ही हुआ, रेडिेशन से कैसर के ट्रीटमेंट जैसा तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत में मॉरल (नैतिक) वैल्यू सिस्टम का आभाव, सुप्त अन्तरात्मा, असहाय व मजबूर-सी अफसर शाही, नारे गढ़ने में मास्टरी, आदि, आदि, कारणों ने एक साथ मिलकर पूरे सरकारी ढांचे, प्रशासनिक तंत्र को छक्कड़ोर दिया, इतना कि अब उसे पटरी पर आने में कई इशक लगेंगे। उदाहरण के लिए, “फोन टैपिंग” का प्रकरण एक और महत्वपूर्ण मामला है, जिसे बारीकी से देखा जाना चाहिए। पहले तो ऐसा

“फुलप्रूफ” सिस्टम तैयार किया गया कि कोई सबूत न रहे कि कोई टैपिंग हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति का फोन “टैप” किया जा सकता है, और अगर टैपिंग की अवधि एक सप्ताह से कम है, तो इस टैपिंग की स्वीकृति के लिए कोई फाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अतः प्रक्रिया यह अपनायी गयी कि पांच-छः दिनों के लिए फोन “टैप” किया गया और फिर एक दो-दिन के लिए फोन को “टैपिंग” की लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर दो दिन बाद पुनः पांच-छः दिन की “टैपिंग लिस्ट” में डाल दिया गया।

गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस टैपिंग को सात दिन से ज्यादा जारी करने की स्वीकृति नहीं देते, तीन महीने के बाद इस टैपिंग का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता था। पर प्रदेश में फोन टैपिंग कांड सिर्फ गैर-कानूनी तरीके से की गई जासूसी का ही एक उदाहरण नहीं है, बल्कि

गहलोत ने किस तरह से फोन टैपिंग का प्रचार-प्रसार करवाया और फिर इस प्रकरण से दूरी बनाए रखने के लिए अपने ही ओ.एस.डी. को निष्कासित किया और पुलिस की जांच झेलने में झोंक दिया।

इस्तीफा देना पड़ा था। परंतु गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस और गृह विभाग को जैसे तोड़ा और मरोड़ा उससे “सत्ता के दुरुपयोग” की परिभाषा ही बदल जाती है।

सरकारी काम-काज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो शायद शुरू से ही रहा होगा, गहलोत ने इस “भ्रष्टाचार” में सबको पार्टनर बना दिया, अफसरशाही, राजनीतिज्ञ आदि। इसकी धुरी बना दिया स्थानीय विधायक को। उदाहरण के लिए, बजरी का अवैध काम, स्थानीय नाके के कर्मचारी, छोटे-मोटे पंच-सरपंच स्तर का नेता, छोटे बड़े कॉन्स्टेबल से लेकर उच्चतम स्थानीय नेता (विधायक, मंत्री) शीर्षस्थ स्थानीय पुलिस अधिकारी (थानेदार) डॉ.जाय.एस.पी., एस.पी.) तथा स्थानीय उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी, सभी की इस “धंधे” में हिस्सेदारी तय कर दी गई और धड़ल्ले से “धंधा” चला। यह “इन्स्टिट्यूशनलाइजेशन” सभी विभागों में प्रचलित हो गया, पर स्थानीय स्तर पर धुरी विधायक/मंत्री को ही रखा गया। क्योंकि, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही, जब पहली बार,

प्रथम कार्यकाल में उन्होंने “डिजायर” कल्चर शुरू किया, कि, किसी भी “ट्रांसफर, पोस्टिंग” के चले आ रहे विषय के लिए जितने विधायक की “डिजायर” को ही महत्व दिया जायेगा, पार्टी के किसी अन्य नेता को नहीं, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ, व कद में राष्ट्रीय स्तर का माना जाता हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व ए.आई.सी.सी. के महासचिव नवल किशोर शर्मा व नरसिम्हाराव सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इस “डिजायर” कल्चर के अपने अनुभव शेयर किये।

“इमरजेंसी” के बाद वे जोधपुर से एम.पी. बने थे, तथा प्यार: दिल्ली ही रहने लगे थे, तब गहलोत ने निष्कर्ष निकाल लिया था, कि कांग्रेस के किसी राजनीतिज्ञ को सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कि दिल्ली के पास, उस मुख्यमंत्री की शिकायतें नहीं पहुंचें और

तीन बार मुख्यमंत्री रहने के कारण वे सरकारी प्रक्रिया से काफी सुपरिचित हो गये थे। सिस्टम को कैसे और कितना तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, अपने राजनीतिक हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यह खूब समझ गये थे, और किस अफसर को दबाव से, किसको प्रलोभन से, किसको व्यक्तिगत सम्बन्धों से फुसलाकर उपयोग में लाया जा सकता है, और यह भी कि यदि अफसर फिर भी काबू नहीं आता तो, उसे कहाँ और किस टांड पर रखा जा सकता है।

ये शिकायतें पहुंचाने का काम विधायक करते हैं। अतः विधायकों को “खुश” रखना प्रथम जिम्मेवारी है, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। अतः अपने प्रथम काल में उन्होंने “डिजायर” कल्चर शुरू किया, किसी भी “ट्रांसफर, पोस्टिंग” के चले आ रहे विषय के लिए जितने विधायक की “डिजायर” को ही महत्व दिया जायेगा, पार्टी के किसी अन्य नेता को नहीं, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ, व कद में राष्ट्रीय स्तर का माना जाता हो।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व ए.आई.सी.सी. के महासचिव नवल किशोर शर्मा व नरसिम्हाराव सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इस “डिजायर” कल्चर के अपने अनुभव शेयर किये। कोटा के भुवनेश चतुर्वेदी, आजीवन अविवाहित रहे पर अपने वृहत् परिवार के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी निभाते रहे। उनका एक भतीजा, जो सरकार की मेडिकल सर्विसेज विंग में डॉक्टर था, डेप्युटेशन पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में “पोस्टेड” था। यह कोई खास बड़ी बात नहीं थी। यह सुविधा, जरा सा भी जो “कनैक्टेड” व्यक्ति था उसके रिश्तेदारों को सदा से मिलती आई है। पर अचानक, भुवनेश चतुर्वेदी के भतीजे का एस.एम.एस. से ट्रांसफर हो गया। रामलुभाया उस समय स्वास्थ्य सचिव थे तथा कोटा में कलैक्टर रह चुके थे और भुवनेश चतुर्वेदी के “महत्व” से अच्छी तरह परिचित थे। तीन चार बार भुवनेश चतुर्वेदी ने अपने भतीजे के एस.एम.एस. अस्पताल से ट्रांसफर को रद्द करने को कहा, रामलुभाया ने आखिर रद्द कर दिया। तब यह प्रशासनिक प्रथा थी, कि हर महत्वपूर्ण ट्रांसफर, चाहे किसी की भी डिजायर आये, सी.एम.ओ. की स्वीकृति से ही होता था। मुख्यमंत्री ने रामलुभाया को तलब किया और पूछा, “ये ट्रांसफर रद्द करने के आदेश कैसे निकले, सी.एम.ओ. ने ऐसे ही कोई “डिजायर” नहीं भेजी थी।” सकुचाते हुए रामलुभाया ने जवाब दिया, “भुवनेश जी कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ व प्रतिष्ठित नेता हैं, उनका कई बार फोन आया, अतः...।” दो टुक़ जवाब मिला रामलुभाया को, “कांग्रेस में कौन वरिष्ठ है और उनकी “रिक्वैस्ट” के बारे में क्या निर्णय लेना है, यह सी.एम.ओ. का कार्य क्षेत्र है, आपका नहीं, आगे से ध्यान रखें।”

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज किशोर तिवाड़ी के दामाद को भी कुछ ऐसा ही मामला था। परंतु परिस्थितियों को वजह से (किसी रिश्तेदार की बीमारी के कारण) दामाद की जयपुर पोस्टिंग चाहते थे। तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री, तिवाड़ी जी से काफी जूनियर थे पार्टी में, अतः तिवाड़ी जी ने पोस्टिंग के लिए बातचीत की तो मालूम पड़ा स्वास्थ्य मंत्री से मिलना होगा। वो बेहिचक मंत्री महोदय से मिलने, मंत्री जी के दफ्तर

पहुंचे। मंत्री ने बहुत आवभगत की, सम्मान दिया, “आप जब नेता थे, तब मैं दूरी उठाने वाला साधारण कार्यकर्ता था। आपके आदेश की तुरन्त पालना होगी।” पर काफी समय बाद भी काम नहीं हुआ तो तिवाड़ी जी ने तहकीकात की, मालूम पड़ा काम तो तभी होगा, जब स्थानीय विधायक अपनी “डिजायर” स्वीकृति लिख कर भेज देगा।

पण्डित नवल किशोर शर्मा का भी कटु अनुभव कुछ ऐसा ही था। वे विधायक थे, आमेर से, तथा जयपुर के उनके वफादार कार्यकर्ता का विधायकपुरी थाने में कुछ जायज काम था। अतः उन्होंने सीधे थानेदार को फोन किया पर काम नहीं हुआ। हार बार कार्यकर्ता नवलजी के पास जाकर पुनः फोन करने का दबाव बनाता रहा। थानेदार का भाई, पी.सी.सी. में विधि सैल का उच्चाधिकारी था, अतः पी.सी.सी. में नवल किशोर शर्मा की वरिष्ठता से खूब परिचित था। पर, थानाधिकारी नवलजी की अवहेलना करता रहा। नवलजी ने अंत में फोन पर गुस्से में काफी जोरों से डांट-डपट की। एक कार्यकर्ता/नेता ने दबी जुबान में कहा, “थानेदार तब तक कुछ नहीं करेगा, बाबूजी, जब तक महेश जोशी उसे निर्देश नहीं देता, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर का चार्ज उसे दे रखा है।”

गहलोत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनकी इस पकड़ में और “निखार” आया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर तो उन्हें इस धारणा पर स्वयं भी पूर्ण विश्वास हो गया, कि राजस्थान में उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कमान उन्हें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और अधिकांश विधायक अब उनके पार्टनर बन चुके थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर

पाठकों को याद दिला दें कि जब फोन टैपिंग के आरोप कर्नाटक सरकार पर लगे थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। परंतु गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस और गृह विभाग को जैसे तोड़ा और मरोड़ा उससे “सत्ता के दुरुपयोग” की परिभाषा ही बदल जाती है। सरकारी काम-काज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो शायद शुरू से रहा होगा, गहलोत ने इस “भ्रष्टाचार” में सबको पार्टनर बना दिया, अफसरशाही, राजनीतिज्ञ आदि। इसकी धुरी

प्रेस को रौब से दबाने की, या प्यार से सुलाने की नैसर्गिक फितरत होती है हर सरकार की। इस प्रवृत्ति के बारे में स्वर्गीय उपराष्ट्रपति कृष्ण कान्त ने ऐसे ही प्रकरण के बारे में राज्यसभा में बड़े सटीक ढंग से कहा था, “जब आप खबरों के प्रवाह को जवाब दे रहे हैं, तब आप, अपने तक जानकारीयां पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं।”

की कुंठा साफ झलक रही थी। गहलोत का वह चुनाव हारना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में गहलोत की जोधपुर से हार, इतिहास में एक मनोरंजक “फुट नोट” बनी, जिसे पुराने लोग आज भी तत्कालीन युवा गहलोत के राजनीतिक गुरू व अपरिपक्वता का प्रतीक मानकर, चटकारे लेते हुए याद करते हैं। पर ग्यारह महीने पहले गहलोत के नेतृत्व में लड़े गये विधानसभा चुनाव में हुई हार “फुट नोट” नहीं, बल्कि देश के प्रजातंत्रिय इतिहास में एक “काले युग” के अंत के रूप में उल्लिखित रहेगी।

यह हार किसी भी तरह एक युवा मंत्री की नादानी, नासमझी, मासुमियत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। क्योंकि, उस सरकार का नेतृत्व एक ऐसा मुख्यमंत्री कर रहा था, जिसकी, सबसे बड़ी “कुवैलिटि” (गुण) उसकी राजनीतिक कुटिलता व प्रशासनिक अनुभव था। जिसका मुख्य ध्येय था, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखना। जो भी इस ध्येय को प्राप्त करने में मददगार था उसके सी खून (भ्रष्टाचार के कारनामे) आदि माफ थे, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो। इस नीति को जायज़ ठहराने

प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति का फोन “टैप” किया जा सकता है, और अगर टैपिंग की अवधि एक सप्ताह से कम है, तो इस टैपिंग की स्वीकृति के लिए कोई फाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अतः प्रक्रिया यह अपनायी गयी कि पांच-छः दिनों के लिए फोन “टैप” किया गया और फिर एक दो-दिन के लिए फोन को “टैपिंग” की लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर दो दिन बाद पुनः पांच-छः दिन की “टैपिंग लिस्ट” में डाल दिया गया। गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस टैपिंग को सात दिन से ज्यादा जारी करने की स्वीकृति नहीं देते, इसलिए तीन महीने के बाद इस टैपिंग का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता था।

के लिए तर्क दिया गया कि, पैसे दिल्ली पहुंचाने पड़ते हैं, तो “कलैक्शन” को करना ही पड़ेगा। “आकलन” तो यह है कि दिल्ली ने इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि, इस रणनीति से हाईकमान को नुकसान ही नुकसान था।

थे, जनता अपना मन किस तरह और कैसे बनाती है। इस “प्रक्रिया” में क्या-क्या “फैक्टर्स” काम करते हैं। उनके पास यह जानकारी भी इकट्ठी हो गई थी कि, राजस्थान में कौन-कौन सी जाति/जात कहाँ-कहाँ बसती हैं और जाति/जात का राजनीतिक दृष्टि से चुनाव में क्या महत्व है। साथ ही लम्बे काल तक दिल्ली में सक्रिय रहने के कारण, पूर्ण आभास था, कि दिल्ली कैसे निर्णय लेती है, प्रदेशों में पार्टी के नेताओं के बारे में। दिल्ली में किसकी चल रही है, माखनलाल फोतेदार की, सीताराम केसरी की, अहमद पटेल की, गुलाम नबी आजाद की या किसी अन्य की। उन्होंने अपने सेक्रेटरी टु. सी.एम., ललित पंवार को, इस पद से हटा दिया था, क्योंकि देर रात को माखन लाल फोतेदार की मां की मृत्यु हो जाने पर पंवार ने उन्हें तुरंत उठाकर यह जानकारी नहीं दी, और सुबह गहलोत को मृत्यु की खबर बताई। गहलोत ने इस घटनाक्रम से उत्पन्न पीड़ा व व्यथा उस समय भरे साथ शेयर की, जब वे घर आये थे, और नये सेक्रेटरी टु सी.एम. के चयन के बारे बात कर रहे थे। उन्होंने पंवार को हटाने का निर्णय ले तो लिया था, पर उनकी पीड़ा यह थी कि, उन्होंने एक योग्य व लायक एस.सी.

हार हुई, जालौर की सीट पर। कलबी “कम्युनिटी” को काफी सख्त नाराजगी थी, “कलबी”, जो कांग्रेस के परम्परागत वफादार समर्थक रहे हैं, जो “कलबी” बाहुल्य सीट से, “कलबी” का टिकट काट कर, एक बाहरी को, अपने पुत्र को, टिकट देने से।

मेदांता हॉस्पिटल में हुए भरे छोटे भाई के कैसर के “ट्रीटमेंट” के दौरान एक बात समझ आई। बत्तीस राउण्ड हुए थे रेडिएशन का एक रेडिएशन के राउण्ड में तीन अलग-अलग पावरफुल रेडिएशन की किरणें, कैसर प्रसित गांठ पर एक साथ पहुंचती थीं, तथा ये तीन किरणें एक साथ मिल कर इतनी पावरफुल बन जाती थीं कि कैसर की गांठ बत्तीस राउण्ड के बाद “डिजाॅव्ल” हो गई थी। राजस्थान में सरकारी कामकाज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तथा जातिवाद/जातवाद सम्भवतया शुरू से ही रहा है। पर, कुछ परम्पराओं का दबाव, लोक लाज की शर्म, अन्तरात्मा की आवाज़, सरकारी कामकाज की प्रक्रिया से पूर्ण परिचय ना होना, कुछ अफसरों की पढ़ाई व एक्सपोज़र राजनीतिज्ञों से ज्यादा व बेहतर होने, ने एक अंकुश का काम किया। राजनीतिज्ञों और नेताओं को मनमानी करने से रोकता प्रारंभिक दिनों में अधिकतर सरकारी अफसर राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, अतः स्थानीय परिस्थितियों से ज्यादा परिचित होने का, जनता की नब्ब समझने

“ट्रांज़ैक्शनरी एप्रोच” (लेन-देन, खरीद-फरोख्त के व्यवहार) के कारण लोग जुड़े तो सही, आखिर सबका सरकार से कुछ न कुछ काम तो रहता है। पर, उनके लम्बे राजनीतिक जीवन में, दिल से कोई साथ नहीं जुड़ा। अतः जब तक पद बना रहा, आस-पास मंडराते रहे, पर, मुख्यमंत्री का पद जाते ही भीड़ छंट गई, और राजनीतिक अस्तित्व, रोगी-शैथ्या से वक्तव्य देने तक सीमित रह गया।

राजनीतिक लाभ के लिए कुटिलता से रचित एक ऐसा प्रकरण है जिससे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की विश्वसनीयता को धूमिल करने का एक षड्यंत्र किया गया। गहलोत सरकार के इशारों पर, पायलट और पायलट गुट की छवि धूमिल करने के लिए दो नेताओं की फोन टैपिंग का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले किसी भी स्थानीय बड़े अखबार या मीडिया हाउस ने फोन टैपिंग की “जैनिवनेस” व उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाए। पंद्रह दिन के परफुल जब यह शोर गुल बिल्कुल ही उठा हो गया कि “पायलट भाजपा में जा रहे हैं”, तब मान-हानि के मुकदमों से डर कर, अखबारों ने यह छाप दिया कि उन्हें फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. ने दी थी। गहलोत का कुछ अंश पहले “वॉट्सएप” पर सरक्युलेट करवाया गया और फिर अखबारों में छपवाया गया। हेरानी की बात है, इन फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से पहले

सेजस्थान महा दिवाली

FIXED
PRICE
GUARANTEED

15 लाख

NO
MIDDLE-MEN

15 लाख

15 लाख

दिवाली पर 15 लाख रेट बढ़ेगी !

— दिवाली बाद करोड़ों में मिलेगी कोठी ! —

SPORTS AMENITIES

- BASKET BALL COURT
- BADMINTON COURT
- SKATING RINK
- LAWN TENNIS COURT
- MINI GOLF
- CRICKET PRACTICE NET
- BOX CRICKET
- JOGGING LOOP
- CYCLING TRACK

OUTDOOR AMENITIES

- RASHI GARDEN
- OPEN AIR THEATRE
- WETLAND PARK
- KID'S PLAY AREA
- SANDPIT
- OPEN GYM
- LAP POOL
- KID'S POOL
- ROOF TOP WALK
- MULTI PURPOSE LAWN
- MEDITATION ZONE
- VOCATIONAL WORKSHOP SPACE
- SENSORY WALK
- NATURE TRAIL
- SAVANNA ELEVATED TRAIL
- PICNIC POINTS
- ADVENTURE PLAY AREA

INDOOR AMENITIES

- TUITION ROOM
- LIBRARY
- ART AREA
- KID'S WORKSHOP AND PLAY AREA
- DISNEY THEME GAME ROOM
- CONFERENCE ROOM
- GYMNASIUM
- YOGA AREA
- CARD AREA
- CHESS AREA
- CARROM AREA
- TABLE TENNIS
- BILLIARDS

वॉक-अप
अपार्टमेंट्स

63.45 लाख से शुरू

कोठी

84.60 लाख से शुरू

गिनती की कुछ ही कोठी बची हैं।



KEDIA
सेजस्थान

KOTHI & WALK-UP APARTMENT

अजमेर रोड़, जयपुर

POSSESSION: DEC. 2025

बड़ी-बड़ी कोठी, बड़े-बड़े फ्लैट

KEDIA®

1800-120-2323

78770-72737

info@kedia.com

www.kedia.com

www.rera.rajasthan.gov.in
RERA No. RAJ/P/2023/2387

SCAN QR FOR
• LOCATION
• ROUTE MAP
• SITE 360 TOUR
• E-BROCHURE
• WALKTHROUGH



*T&C Apply

विचार बिन्दु

शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं, किन्तु जो उसके अनुसार आचरण करता है वो ही वस्तुतः विद्वान है। -अज्ञात

त्योहारी सीज़न में ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें

हमारे देश में घर-घर में डिजिटल क्रांति प्रवेश कर चुकी है। अब हमारे खरीद फरोख्त के लगभग सभी काम डिजिटली होने लगे हैं। वजह से बुजुर्ग तक के हाथों में स्मार्ट फोन आने से अब शायद ही कुछ ऐसी चीज बची हो जिसके लिए आप डिजिटल पेमेंट ना करते हो। लोग केश रखने के बजाय डिजिटली पेमेंट देना ज्यादा पसंद करते हैं। इस समय देश में त्योहारी सीज़न चल रहा है जो नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक चलेगा। इस दौरान लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी का जबरदस्त क्रेच बना हुआ है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दर्जनों प्लेटफॉर्म पर जोरदार सेल का धमाका देखने को मिल रहा है। लोग धड़ाधड़ खरीदारी में जुटे हैं। प्रतिदिन लाखों-करोड़ों रुपयों की खरीदारी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही त्योहारी सीज़न में खरीदारी के दौरान डिजिटल पेमेंट फ्राँड का जोखिम भी बढ़ गया है। लोग आकर्षक तुलने वाले ऑफर्स और डिस्काउंट्स के चलते लोग भारी खरीदारी त्योहारी सीज़न में करते हैं। एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में कई बार उपभोक्ता प्लेटफॉर्म की वैधता को जांच को नजरअंदाज कर देते हैं। फ्राँड होने का खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। डिजिटल पेमेंट्स के जरिए लोगों को धोखा देकर फंसाना भी आसान हो गया है। धोखाधड़ी के तरीके भी अब काफी आसान हो गए हैं। इस बीच साइबर जालसाज भी काफी सक्रिय हो गए हैं और साइबर अपराध को अंजाम देने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उपभोक्ताओं को ऑफलाइन खरीदारी की अपेक्षा ऑनलाइन खरीदारी करना अधिक पसंद आता है। ऑनलाइन खरीदारी करना फायदेमंद होता है जहां अपनी पसंद की और कम कीमत पर कई वैराइटी देखने को मिल जाती है। लेकिन कई बार ऑनलाइन खरीदारी करना भारी भी पड़ जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल शुरू होते ही जालसाज भी सक्रीय हो जाते हैं। जो आपको एक गलती पर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। मीडिया में ऐसी घटनाओं के समाचार रोज ही पढ़ने को मिल रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट के दौरान हर स्तर पर सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि साइबर फ्राइड से बचा जा सके। डिजिटल पेमेंट करें तो आप खास तौर पर ध्यान रखें, जिनसे आपको फ्राँड से बचने में मदद मिलेगी। आप किसी लिंक के जरिए या किसी ऐप के जरिए डिजिटल पेमेंट कर रहे हों वह ध्यान रखे यह पेमेंट सुरक्षित है या नहीं। उस कंपनी के बारे में ऑनलाइन रिव्यू चेक करें। उस वेबसाइट के बारे में पता करें। इस सीज़न में खरीदारी के दौरान सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।

भारत में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसके बाद लगातार देश इस क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाये हुए है। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर वन बन गया है और इससे ग्रामीण

अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। तेजी से बढ़ता डिजिटल लेनदेन बढ़ती हुई खपत को दर्शाता है। यह डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए भी अच्छा है। आरबीआई के डाटा के अनुसार देश भर में पेमेंट परफॉर्मिस और पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में वृद्धि की वजह से डिजिटल पेमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि सभी मापदंडों में हुई है। डाटा के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक देश भर में डिजिटल पेमेंट में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2024 के अंत में 445.5 पर था, जबकि सितंबर 2023 में 418.77 और मार्च 2023 में 395.57 था। भारत में मोबाइल पेमेंट स्मार्टफोन के आने और इंटरनेट की

बढ़ती पहुंच के बाद बहुत आसान हो गया। विशेषकर युवाओं में मोबाइल से भुगतान बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। ग्लोबल डेटा के मुताबिक 2028 तक भारत में मोबाइल वॉलेट के माध्यम से भुगतान 531.8 ट्रिलियन रुपये के आंकड़े को पार करने का अनुमान है।

एक अधिकृत जानकारी के अनुसार देश भर में पेमेंट परफॉर्मिस और पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ढांचे में वृद्धि की वजह से डिजिटल पेमेंट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह वृद्धि सभी मापदंडों में हुई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले पांच महीनों में डिजिटल पेमेंट का मूल्य बढ़कर 1,669 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसी अवधि के दौरान डिजिटल पेमेंट का लेन-देन 8,659 करोड़ तक पहुंच गया। यूपीआई लेन-देन का मूल्य 138 प्रतिशत की सीएजीआर पर 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 200 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा पिछले 5 महीनों में कुल लेन-देन का मूल्य बढ़कर 101 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यूपीआई ने देश में डिजिटल पेमेंट में क्रांति ला दी है जहां वित्त वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 129 प्रतिशत की सीएजीआर से 13,116 करोड़ हो गया है। जैसे तेज पेमेंट सिस्टम को अपनाने में तेजी लाने के प्रयासों ने वित्तीय लेन-देन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिससे लाखों लोगों के लिए रीयल-टाइम, सुरक्षित और सीमलेस पेमेंट संभव हुआ है। मार्केट रिसर्च फर्म डेटाम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार इस साल त्योहारी सीज़न में ऑनलाइन बिक्री 12 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 9.7 बिलियन डॉलर से 23 प्रतिशत अधिक है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में तीस करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन भुगतान करते हैं। दुकानदार और ऑनलाइन कम्पनियां जहां इन त्योहारों में आकर्षक ऑफर तथा डिस्काउंट की पेशकश कर ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करती हैं, वहीं ग्राहक भी इन आकर्षक ऑफरों का लाभ उठाकर जमकर खरीदारी करते हैं। सरकारी बैंकों सहित कई कम्पनियां और निम्ता उपभोक्ताओं को लुभावनी छूट से भी लामान्वित कर रहे हैं। खुदरा व्यापारी ऑनलाइन सेल का विरोध कर रहे हैं और अपने व्यापार के चौपट होने की दुहाई दे रहे हैं मगर उपभोक्ता ऑनलाइन व्यापार से खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें बाजार की धकमपेल से छुटकारा मिल रहा है। ऑनलाइन सेल में सामान सस्ता जरूर मिल रहा है मगर उपभोक्ता को सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि उगी करने वाले गिरोह भी आगे हुए हैं। जो भोले भले लोगों को सस्ते माल के चक्कर में फंसा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसे में लोगों ने सतर्कता नहीं रखी तो सस्ते में माल खरीदना महंगा भी पड़ सकता है।

-अतिथि संपादक, बाल मुकुन्द ओझा वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

प्रजातंत्र में संसद, सड़क और संस्कृति



प्रो. कैलाश सोहानी

सैकड़ों वर्षों की गुलामी और गरीबी से मुक्ति के लिए लगभग 200 वर्षों के लम्बे संघर्ष के बाद 1947 में जाकर आजाद भारत का स्वयं साकार हुआ। आजाद भारत किस मार्ग पर चलेगा इसके लिए प्रजातंत्र के तत्कालीन आदर्शपूर्ण पुरोधाओं ने भारतीय संविधान कानिमांण किया। उसी संविधान के तहत देश को देश के मतदाताओं से सुजित संसद जैसा एक शानदार तौहफा प्राप्त हुआ। संसद कोई इमारत नहीं है अपितु

भारत के मतदाताओं की भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ने भारतीय प्रजातंत्र को दुनियाँ की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में श्रेष्ठ पायदान पर पहुंचाया है। संसद पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अपना मत एवं विचार प्रकट करने के लिए श्रेष्ठ एवं सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है। हमारी संसद में अनेक बार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, परिचर्चा एवं बहस बड़ी विद्वत्तापूर्ण एवं रोचक रही है। संसद की बहस को गरिमा प्रदान करने वालों में प्रमुख हैं - बी.के. कृष्णामेनन, पीलू मोदी, फिरोज गाँधी, राममनोहर लोहिया, मधु लिम्पये, सोमनाथ चटर्जी, अटल बिहार वाजपेयी, प्रमोद महाजन, सुभमा स्वराज, सुधांशु त्रिवेदी। साथ ही सांसदों द्वारा आये दिन होने वाली नारेबाजी एवं बहिष्कार से संसद का बड़भूषण समय बहुत खराब होता है। इस प्रकार का शोर-शराबा संसद की गरिमा एवं हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। संसद की गरिमा बनाये रखने की जिम्मेदारी पक्ष एवं विपक्ष दोनों की है,

इसके लिए सभी सांसदों से मर्यादित एवं अनुशासित आचरण अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में लोकसभा अध्यक्ष से भी यह अपेक्षा रहती है कि वे विपक्ष को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय एवं अवसर प्रदान करें। सौभाग्य से यह काम हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष बखुबी निभा रहे हैं। एतद्दर्थ विपक्षी सांसद उनके प्रति विश्वास एवं श्रद्धा का भाव रखते हैं। अब मैं आलेख के मूल विषय पर आता हूँ कि प्रजातंत्र में संसद के साथ-साथ सड़क की राजनीति का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान एवं वजूद है। जब विपक्ष को यह लगता है कि संसद के माध्यम से वह अपनी बात कह नहीं पा रहा है तो फिर विपक्ष धरना, प्रदर्शन, बन्द इत्यादि के माध्यम से सड़क की राजनीति प्रारम्भ करता है, जिसे हमारे देश में पर्याप्त प्रेस कवरेज भी मिल जाता है। अतः विपक्ष अपनी बात मतदाताओं तक पहुँचाने में सफल भी होता है। 1972-74 में जयप्रकाश नारायण का जन आन्दोलन, 1990-91 में श्री राम जन्मभूमि के लिए लालकृष्ण आडवाणी की रथ-यात्रा,

2013-14 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अत्रा हज़ारों के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन, 2023-24 में राहुल गान्धी की भारत जोड़ो यात्रा आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि संसद के बाहर भी अपनी बात को बहुत बेबाक तरीके से समझने के समक्ष रखा जा सकता है। संसद और सड़क की राजनीति की श्रेष्ठता के लिए हमें हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को अपेक्षा याद रखना होगा। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप ही संसद एवं सड़क पर अनुशासित संवाद एवं आचरण होना चाहिये। निःसन्देह प्रजातंत्र को जीवन्त बनाये रखने के लिए धरना, प्रदर्शन, आन्दोलन सभी आवश्यक हैं परंतु आन्दोलन में भी हमें हमारी संस्कृति एवं मूल्यों को नहीं भूलना चाहिये। आन्दोलन का मतलब अनुशासनीयता नहीं है। जैसे किसान आन्दोलन के समय राष्ट्रीय सरकार को अवरुद्ध करना, राजस्थान में आरक्षण को लेकर रेलों के आवागमन को बाधित करना, दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क पर

किये धरना-प्रदर्शन से महीनों तक दिल्लीवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। आन्दोलन के नाम पर आगजनी, तोड़फोड़, बाजार बन्द, चक्का जाम आदि शुद्ध अनुशासनहीनता है। यह प्रजातंत्र के दुरुपयोग के साथ-साथ हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की अवहेलना भी है। व्यक्ति या समूह सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं परन्तु आम नागरिकों को उनके आन्दोलन से कोई असुविधा एवं कष्ट नहीं होना चाहिये। किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान न तो किसी नागरिक को होना चाहिये और न ही सरकार को। यह देखा भी आंदोलनकारियों का कर्तव्य है। भारतीय प्रजातंत्र के अंतर्गत आने वाले नी रेलवे स्टेशनों पर भी बुनियादी सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग

महाकुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के इंतजाम से सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग

प्रयाग महाकुंभ-2025 : सांस्कृतिक महत्व



राजेन्द्र जोशी

अमृत कहाँ बरसेगा। यह पहले से तय है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है - कला, ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिह्न है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। इस बार कुंभ के तीर पर पेश करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जहाँ महाकुंभ में पॉलिथीन को प्रतिबंधित किए जाने की तैयारी है, वहीं तीन लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं।

इन् पाँचों को सरकार संरक्षित भी करेगी। महाकुंभ के आयोजन हेतु 5154 करोड़ की 327 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके साथ ही 1264 करोड़ की 75 विभागीय परियोजनाओं पर भी काम प्रारंभ हो चुका है। महाकुंभ से जुड़ी सभी स्थाई और अस्थायी परियोजनाओं को अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अनुभवी अधिकारियों की टीम दिन-रात काम में जुटी है। इन् प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम - 2019 में आयोजित दिव्य तथा बेसन बूंदी के लड्डू, वनस्पती ची के नमूने लिए गए। इस दौरान श्याम प्रेमी शुद्ध मिष्ठान भंडार के यहां से केशर मावा पेड़ा, शेखावत मिष्ठान

एक सार्थक चर्चा का आयोजन किया। जैसे भी बीकानेर और संगम का एक महत्वपूर्ण रिश्ता जुड़ता है, प्रयाग में तीन नदियों का संगम है, सहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इतिहास यह कहता है कि थार के मरुस्थल बीकानेर में कभी सरस्वती नदी का प्रवाह हुआ करता था। इस अभी सरस्वती नदी की गोद में रह रहे हैं। इसका मतलब हम भी कल्पवृक्ष का हिस्सा हैं। महाकुंभ मेला भव्य - दिव्य और नव्य थीम पर आयोजित हो रहा है। 400 मिलियन लोगों की संभावना 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में शामिल होंगे।

संगम की पवित्र धरती प्रयाग का महाकुंभ 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक संचालित होगा। कुल 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में देश-विदेश से हजारों-हजार श्रद्धालु प्रयागराज पहुँच रहे हैं। महाकुंभ की तैयारियाँ तेज हो गई हैं, 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पॉलिथीन फ्री और डीन कुंभ के तौर पर पेश करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए जहाँ महाकुंभ में पॉलिथीन को प्रतिबंधित किए जाने की तैयारी है, वहीं तीन लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं।

इन् पाँचों को सरकार संरक्षित भी करेगी। महाकुंभ के आयोजन हेतु 5154 करोड़ की 327 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके साथ ही 1264 करोड़ की 75 विभागीय परियोजनाओं पर भी काम प्रारंभ हो चुका है। महाकुंभ से जुड़ी सभी स्थाई और अस्थायी परियोजनाओं को अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अनुभवी अधिकारियों की टीम दिन-रात काम में जुटी है। इन् प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम - 2019 में आयोजित दिव्य तथा बेसन बूंदी के लड्डू, वनस्पती ची के नमूने लिए गए। इस दौरान श्याम प्रेमी शुद्ध मिष्ठान भंडार के यहां से केशर मावा पेड़ा, शेखावत मिष्ठान

क्षेत्रफल जहाँ बढ़ाया जा रहा है, वहीं मेले में अतिरिक्त सुविधाएँ भी मुहैया कराए जाने की तैयारी है। मेले का क्षेत्रफल बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। कुल 25 सेक्टर में मेला बसाया जाएगा, जबकि 1900 हेक्टेयर में छह पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ मेले में 25000 लोगों के लिए पब्लिक अकीमोडेशन, मोटरबोट, चेंजिंग रूम, पूजा स्थल और फ्लोटिंग जेटी बनाई जाएगी। मेले में इस बार 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनेंगे, पहली बार यमुना नदी के वीआईपी घाट पर पक्के घाट का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर भी पक्का घाट बन रहा है। यातायात की समस्या को देखते हुए तेलियरंग से संगम क्षेत्र तक 13 किलोमीटर का रिक्त फ्रेट भी बनाया जा रहा है। वर्ष भर घाटों पर जल का प्रवाह बना रहे इसके लिए ड्रेजिंग भी कराई गई। महाकुंभ से जुड़ी अन्य परियोजनाओं में सड़कों और चौराहों का चौड़ीकरण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट विस्तार के साथ ही अनेक फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं।

महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अक्षय वट, पाताल पुरी, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर, श्रृंगवेपुर धाम और भारद्वाज कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जा रहा है। अक्टूबर - दिसंबर 2024 तक मेले में सभी संस्थाओं को जमीन और सुविधाओं का आवंटन कर दिया जाएगा। इस बार खास तौर पर ऑनलाइन साँफवेयर के जरिए जमीनों और सुविधाओं के आवंटन की तैयारी की गई है।

श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था - श्रद्धालु और पर्यटक सुगमता से महाकुंभ मेले में आकर सुरक्षित वापस जा सके इसके लिए तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट पर जहाँ एनए टर्मिनल बनाया जा रहा है, वहीं एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ मेले तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही सड़क को विश्व स्तरीय स्मार्ट रोड बनाया जा

जाएगा। जनवरी-फरवरी 2025 में महाकुंभ के पावन 45 दिनों के दौरान 400 मिलियन लोगों का एकत्रीकरण, जो अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त जनसंख्या के बराबर होगा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या, जो 250 मिलियन है, का 1.6 गुना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, 67,000 स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने वाले इस टेंट शहर में पर्यटकों की सेवा के लिए 2,000 टेंट और 25,000 सार्वजनिक आवास होंगे।

स्वच्छता का माडल होगा महाकुंभ। स्वच्छता के माडल के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 1.45 लाख शौचालय बनाए जाएंगे।

भव्य-दिव्य और नव्य थीम। पिछले कुंभ 2019 का थीम दिव्य व भव्य कुंभ था। इस बार 2025 के महाकुंभ में एक शब्द और जोड़ दिया गया है। भव्य-दिव्य और नव्य महाकुंभ इस बार का थीम होगा। सरकार की ओर से इस पर स्वीकृति भी दे दी गई है। सरकार महाकुंभ-2025 को भव्य, दिव्य और नव्य स्वरूप दे रही है। कुंभ नगर को जिले का दर्जा मिलेगा और यहाँ जिला स्तरीय अधिकारी तैनात होंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए कुंभ क्षेत्र का विस्तार किया गया है। महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने के अनुमान के मुताबिक ही बसावट में बदलाव किया गया है।

कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार 4000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में होगा। पिछला कुंभ 3000 हेक्टेयर में बसा था। इस बार 25 सेक्टर में महाकुंभ बसाया जाएगा। सेक्टर का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने के लिए गंगा पर 30 पॉइंट पुल बनेंगे। पिछली बार 22 पॉइंट पुल बने थे, जबकि इस बार 30 पॉइंट पुलों का निर्माण होगा।

-राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद्-साहित्यकार

खाटूश्यामजी में मिठाई की दुकानों का निरीक्षण, 360 किलो दूषित मिठाई नष्ट कराई

बेसन के लड्डू, बेसन की चक्की दूषित मिली, सोयाबिन तेल खराब मिला

खाटूश्यामजी/सीकर, (निर्स)। दीपावली त्योहार पर आमजन को शुद्ध व ताजा खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा व सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह के निदेशों में शुक्रवार को चिकित्सा विभाग की ओर से खाटूश्यामजी में कार्रवाई की गई। सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह ने बताया कि खाटूश्यामजी में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुये 360 किलो दूषित मिठाई की नष्ट की साथ ही बूंदी के

लड्डू व सोयाबीन के नमूने लिए। एफएसओ मदनलाल बाजिया, महमूद अली व नंदराम मीणा ने अंतिमा स्वीट स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान 250 किलो बेसन के लड्डू, 110 किलो बेसन की चक्की दूषित पाई गई तथा 25 लीटर सोयाबिन तेल खराब पाया गया, जिनको मौके पर ही नष्ट करवाया गया तथा बेसन बूंदी के लड्डू, वनस्पती ची के नमूने लिए गए। इस दौरान श्याम प्रेमी शुद्ध मिष्ठान भंडार के यहां से केशर मावा पेड़ा, शेखावत मिष्ठान

दूषित मिठाइयों को मौके पर नष्ट कराया, "शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान" के तहत कार्रवाई की

कारोबारियों को दीपावली पर्व पर आवश्यकता से अधिक मिठाई नहीं बनाने का उपायों का उपयोग एफएसएसआई के निर्धारित मानकों के अनुसार ही करने के लिए पाबंद किया गया। टीम में अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी नन्दराम मीणा, श्रवण कुमार, दिनेश कुमार, राजेन्द्र सिंह, दिलीप सिंह, कुलदीप सिंह, सुमेर सिंह व अरविंद फोउट शामिल रहे।

रामगढ़ शेखावाटी तहसील में 26 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये

: जिला रसद अधिकारी सीकर नरेश शर्मा ने बताया कि जिले में अवैध एलपीजी रिफिलिंग एवं दुरुपयोग को रोकने के लिए शुक्रवार को जिला रसद विभाग की 6 प्रवर्तन निरीक्षकों की टीम ने रामगढ़ शेखावाटी तहसील में कार्रवाई के दौरान 26 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गए जो घरेलू गैस सिलेण्डर का होटल, मिठाई बनाने आदि में व्यवसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि रसद विभाग की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए युवा आगे आएँ : राज्यपाल बागड़े

अचरोल, (निर्स)। अपेक्स युनिवर्सिटी के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन अचरोल कैम्पस में हुआ, जहाँ प्रशासनिक भवन से दीक्षांत परेड प्रारंभ होकर दीक्षांत स्थल तक पहुंची। समारोह का प्रारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, अध्यक्षता कर रहे युनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ. रवि जूनीवाल और विशिष्ट अतिथि आचार्य बालकृष्ण, कुलपति पंतजलि

विश्वविद्यालय, हरिद्वार एवं निहालचंद एभूतपूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर ने बेस्ट स्टूडेंट्स को डॉ. सागरमल जूनीवाल मेमोरियल अवार्ड सहित विभिन्न संकायों में 15 टॉपर्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। आयुर्वेद, योग के क्षेत्र में नए अनुसंधान को बढ़ावा देने और स्वस्थ सेवाओं में योगदान देने के लिए अपने असाधारण और अविस्मरणीय योगदान के लिए आचार्य बालकृष्ण

एवं सबसे कम उम्र में लोकसभा सांसद बने और पाँच बार सांसद रह चुके भूतपूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री निहालचंद को समाज के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीपू लिटणू की मानद उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। विद्या वही है जो जीवन की समस्याओं का सटीक हल खोजने में

सहायता करे। मुझे प्रसन्नता है कि अपेक्स विश्वविद्यालय इसी दिशा में काम कर रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को आगे लाकर शिक्षा देने का आपका प्रयास सराहनीय है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत ने विश्व को बहुत से नवाचार और आविष्कार दिए हैं। आप इस महान परम्परा को आगे बढ़ाएँ। ज्ञान का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है, आप देश

को आगे ले जाएँ। मैं आपको विभिन्न स्तरों पर उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। विशिष्ट अतिथि आचार्य बालकृष्ण ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। युनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉ रवि जूनीवाल ने अपने दीक्षांत भाषण में डिग्री प्राप्त करने सभी प्रतिभाओं को बधाई दी। इस दीक्षांत समारोह में यूजीए पीजी एवं रिसर्च स्टूडेंट्स को डिग्रियाँ वितरित की गईं।

राशिफल शनिवार 26 अक्टूबर, 2024

पंडित अनिल शर्मा

कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत् 2081, आश्लेषा नक्षत्र प्रातः 9:46 तक, शुक्ल योग रविवार प्रातः 5:57 तक, वणिज करण सायं 4:23 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 9:46 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-मिथुन, बुध-तुला, गुरु-वृष, शुक-वृश्चिक, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज ज्वालामुखी योग प्रातः 9:46 तक है। भद्रा सायं 4:23 से आरम्भ होगी। महापात योग रात्रि 2:10 से आरम्भ होगी।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 8:00 से 9:24 तक, चर 12:11 से 1:34 तक, लाभ-अमृत 1:34 से 4:21 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 4:37, सूर्यास्त 5:45

मेष

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

सिंह

नैकरिपेशा व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

धनु

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

वृष

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी।

कन्या

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय बना रहेगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मकर

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य विगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मिथुन

आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बचने लगेगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

तुला

व्यावसायिक कार्यों में सफलता होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा।

कुंभ

घर-परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

नैकरिपेशा व्यक्तियों को भाग्यी लड्डू रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बचने लगेगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

मीन

स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक बर्ता सफल रहेगी।

महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के चुनाव नतीजों का असर नहीं होगा

क्योंकि हरियाणा में भाजपा का मुकाबला सीधे कांग्रेस से था, पर, महाराष्ट्र में कांग्रेस, गठबंधन की जूनियर पार्टनर मात्र है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर दो सी अठ्यासी सीटों वाले महाराष्ट्र तथा 81 सीटों वाले आदिवासी बहुल झारखंड के विधानसभा चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं, जब हरियाणा के चौका देने वाले परिणामों ने इन दोनों राज्यों के चुनावों को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। महाराष्ट्र में विरोधाभास साफ जाहिर है। एक तरफ तो भाजपा, एकनाथ शिंदे सरकार, जो भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग तथा लोक-लुभावन योजनाओं के नाम पर राजकोष को खाली कर देने के आरोपों से जुड़ रही है, को समर्थन दे रही है। वहीं बिड़म्बना यह है कि झारखंड में भाजपा सत्ता में आने के लिये जे.एम.एम. सरकार पर यही आरोप लगा रही है।

हरियाणा में, भाजपा ने कांटे की टक्कर के तहत बिखरी हुई कांग्रेस को मात दे दी थी। उसका आंशिक कारण तो यह रहा कि कांग्रेस, भाजपा से कुल 22,000 वोटों के अन्तर से 9 सीटें हार गईं, जिसमें इंडियन नेशनल लोक दल (आई.एन.एल.डी.) से हारी सीट भी

■ महाराष्ट्र में भाजपा के पास शरद पवार व उद्धव ठाकरे जैसा करिश्माई नेता भी नहीं है। हालांकि भाजपा ने शरद पवार को कमजोर करने के लिए अजित पवार का और उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए एकनाथ शिंदे का प्रयोग किया, पर, उसे सफलता नहीं मिली।

■ जबकि, हरियाणा में भाजपा का सामना धरातल पर बिखरी हुई व गुटबाजी से त्रस्त कांग्रेस से था, यही वजह रही कि कांटे की टक्कर में भाजपा ने जीत हासिल कर ली।

शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र एवं झारखंड की चुनावी स्थितियाँ पूरी तरह भिन्न हैं। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस, गठबंधन में जूनियर पार्टनर की भूमिका में है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे तथा शरद पवार एवं झारखंड में हेमन्त सोरेन की टक्कर के करिश्माई नेता भाजपा के पास नहीं है, इसीलिये भाजपा पूरी तरह से नरेन्द्र मोदी की छवि और अमित शाह की राजनैतिक चतुराई पर भरोसा करने के लिए मजबूर है।

महायुति गठबंधन में अजित पवार सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं। अभी हाल ही तक, वे अपने चाचा शरद पवार

के गुट में लौटने के लिये, उनसे समझौता वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे एन.सी.पी. को तोड़कर, भाजपा के पक्ष में गये थे, उस समय ई.डी. 80,000 करोड़ रूपए के सिंचाई घोटाले में उनके खिलाफ जांच करने वाला था। लेकिन उनकी सारी पेशानियाँ भाजपा में शामिल होने के बाद समाप्त हो गईं। दरअसल, अजित पवार का प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्रों में ही है, जबकि शरद पवार का जनाधार व्यापक और मजबूत है। पिछले लोकसभा चुनावों में, अजित पवार जैसे-तैसे एक सीट जीत पाये थे तथा

उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले से बारामती सीट पर बुरी तरह हार गई थीं।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिव सेना लोकसभा चुनाव में 7 सीटें तथा भाजपा मात्र 9 सीटें जीत पाई थी। शिंदे गुट, लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर, अब सीटों के आनुपातिक आवंटन पर जोर दे रहा है। लेकिन चुनावों की घोषणा होते ही, भाजपा ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिये हैं तथा शिंदे और पवार गुट को दरकिनार कर दिया है। बताया जाता है कि भाजपा ने दिल्ली में शिंदे को यह स्पष्ट कर दिया था कि भाजपा ज्यादा सीटें प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका अर्थोन्मुख उप मुख्यमंत्री बनाकर, एक बड़ी कुर्बानी दी है। भाजपा यह दलील देती है कि लोकसभा चुनावों में शिंदे गुट को ज्यादातर वोट उत्तर भारत के प्रवासियों से मिले थे, जो परम्परागत रूप से मुम्बई तथा अन्य क्षेत्रों में भाजपा का मजबूत जनाधार हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एडिशनल एस.पी. ने 34 लाख में राजीनामा कराया- डी.जी. जाँच करें

जयपुर, 25 अक्टूबर राजस्थान हाईकोर्ट ने सर्वाई माधोपुर के गंगापुर थाने में दर्ज मामले में बिना जांच अधिकारी होते हुए, तत्कालीन स्थानीय एडिशनल एस.पी. की ओर से 34 लाख रूपए में पक्षकारों के बीच राजीनामा कराने के मामले में डी.जी.पी. को जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से वर्दी में नोटों के साथ बैठकर पक्षकारों में राजीनामा कराने को गंभीर माना है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी

■ हाई कोर्ट ने कहा, एडिशनल एस.पी. जाँच अधिकारी नहीं थे, पर वर्दी में नोटों के साथ पक्षकारों के साथ बैठकर समझौता कराया, यह गंभीर मामला है।

का मध्यस्थता कराना व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में डी.जी.पी. से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मामले की पुनः जांच कराएँ अन्यथा पूर्व में तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे एडिशनल एस.पी. की सेवा पुस्तिका में लगाया जाए इसके साथ ही, अदालत ने मामले के आरोपी पवन कुमार को जमानत पर रिहा करने को कहा है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने यह (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्व अधिकारी-अधिशायी अधिकारी परीक्षा निरस्त

आर.पी.एस.सी. ने हाईटैक डिवाइस से नकल की पुष्टी होने पर यह निर्णय लिया

अजमेर, 25 अक्टूबर (कास)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के आयोजन के दौरान गोपनीयता भंग होने की जानकारी के बाद, राजस्व अधिकारी ग्रेड- द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 (14 मई 2023) को निरस्त कर दिया गया है। परीक्षा के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में आयोग ने 12 जून 2024 को शिकायतों की जांच के लिए ए.टी.एस. एवं एस.ओ. जी. को लिखा था। आयोग अब समस्त आवेदित अभ्यर्थियों के लिए 23 मार्च 2025 को पुनः परीक्षा का आयोजन करेगा।

आयोग सचिव के अनुसार, आयोग ने पाया कि परीक्षा आयोजन के दौरान ही कतिपय परीक्षा केन्द्रों पर वांछित शुचिता का पूर्ण अभाव रहा है। कई अभ्यर्थियों द्वारा ब्युत्थ से नकल करने के संबंध में दर्ज तीन प्राथमिक रिपोर्टों, उनके अनुसंधान उपरान्त, अपराध प्रमाणित पाये जाने पर स्पष्ट हुआ है कि राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) परीक्षा, 2022 (परीक्षा 14 मई

■ अतिरिक्त महानिदेशक एस.ओ.जी. ने 28 अगस्त की रिपोर्ट में आयोग को बताया कि परीक्षा की गोपनीयता के संबंध में गंभीर तथ्य सामने आये हैं।

■ समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा 23 मार्च 2021 को होगी।

2023) को गोपनीयता खंडित हुई है। इसीलिए आयोग ने राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा, 2022 को निरस्त कर समस्त आवेदित अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा आयोजित किये जाने का निर्णय लिया है।

आयोग द्वारा 14 मई 2023 को 111 पदों के लिए आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशायी अधिकारी वर्ग-चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा-2022 में 1,96,483 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से जारी सूची में कुल 311 अभ्यर्थी सम्मिलित थे।

दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों के संदिग्ध प्रतीत होने पर आयोग ने भी 02 अगस्त 2024 से

दिनांक 08 अगस्त 2024 तक अनेक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की पुनः जांच कर पुष्टताखे नोट तैयार किया और 14 अगस्त 2024 को अतिरिक्त महानिदेशक, ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी. को अंतिम अनुसंधान करने के लिए लिखा था। इस क्रम में को अतिरिक्त एस.ओ.जी., जयपुर ने भी एस.ओ.जी. थाना जयपुर में 19 अक्टूबर 2024 को एफ.आई.आर. संख्या 66/2024 दर्ज की गई है एवं अनेक अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।

क्या सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार पाकिस्तान से आए थे?

मुम्बई पुलिस को शक है कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे गए थे

मुम्बई, 25 अक्टूबर महाराष्ट्र के राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के दौरान हथियारों के पास पांच अलग-अलग तरह की पिस्तौलें थीं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मामले में गिरफ्तार आरोपी राम कर्नौजिया के घर से एक पिस्तौल मिली। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। मुंबई पुलिस ने संदेह जताया है कि ये पिस्तौलें पाकिस्तान से आई हैं। पुलिस को शक है कि ये ड्रोन के जरिए भेजी गईं हैं। इन हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गईं हैं।

पुलिस के मुताबिक, पिस्टल रायगढ़ जिले के प्लसपे नाम की जगह से बरामद की गई है, जहाँ पर आरोपी राम कर्नौजिया का किराए का घर है। पुलिस को इस मामले में अब कुल 4 पिस्टल मिल चुकी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान पता चला कि हथियारों

■ मुम्बई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि हथियारों की तस्वीरें राजस्थान पुलिस को भी भेजी गईं हैं।

■ मुम्बई क्राइम ब्रांच को जाँच के दौरान पता चला कि हथियारों के पास 5 अलग-अलग तरह की पिस्तौलें हैं। पुलिस चार पिस्तौलें बरामद कर चुकी है।

के पास कुल 5 अलग-अलग तरह की पिस्टल थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शूटर्स के मोबाइल को जब खंगाला गया तो उनमें पिस्तौलों की तस्वीरें मिली थीं। पुछताछ के बाद क्राइम ब्रांच अन्य पिस्तौलें ढूँढने में लग गई। मुंबई क्राइम ब्रांच को ऑस्ट्रेलिया में ब्रेटा पिस्तौल की तलाश है।

पुलिस के अनुसार, हरियाणा के रहने वाले गुरमेल बलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश के निवासी धर्मराज कश्यप के साथ आरोपी शिवकुमार गौतम ने बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई थी, जबकि पुणे के प्रवीण लोनकर के भाई शुभम का संबंध कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से

है। उसने और अन्य आरोपियों ने हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी और शूटर्स को हथियारों की सप्लाई की थी। हत्या से पहले सिद्दीकी की सुरक्षा में मौजूद पुलिस अधिकारी पर मिर्च पोडर फेंका गया था। वहीं, पुलिस के अनुसार, पुणे के एक स्क्रेप डीलर हरीश कुमार निसाद ने हत्या के लिए वित्तीय मदद दी थी। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम के साथ ही मुख्य आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद जोशान अख्तर फिलहाल फरार हैं।

पुलिस सूत्रों बताया कि मुख्य आरोपी जोशान अख्तर अन्य सभी आरोपियों के संपर्क में था और उसने काम पूरा होने पर उन्हें मोटी रकम और फॉरैन टूर का वादा किया था।

‘विभागीय कार्यवाही लंबित होने पर विदेश यात्रा से नहीं रोक सकते’

जयपुर, 25 अक्टूबर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि विभागीय कार्यवाही का लंबित होना, किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकने का आधार नहीं हो सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार का दायरा व्यापक है, जिसमें विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया

■ राजस्थान हाई कोर्ट ने नीरज सक्सेना की याचिका पर बेटे से मिलने सिंगापुर जाने की सशर्त अनुमति दी।

के अनुसार ही विदेश जाने से वंचित किया जा सकता है। विदेश जाने की स्वतंत्रता का सामाजिक महत्व है, यह महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक उसके बेटे से मिलने के लिए सिंगापुर जाने की सशर्त अनुमति भी दे दी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश नीरज सक्सेना की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘घर का जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध’

नोबल पुरस्कार विजेता कोरिअन लेखक की किताब कोरिया में ही प्रतिबंधित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर “कोरिअन हैरलड” की चाई जॉंग हून ने सिओल से खबर दी है कि दक्षिण कोरिया की उपन्यासकार हन कांग को 2024 का साहित्य का नोबल पुरस्कार मिलने के बाद देश भर में उल्लास का माहौल है, किन्तु, इस सबके बीच कांग की एक किताब को लेकर भारी वाद विवाद छिड़ गया है, जिसे “युवाओं के लिए हानिकारक” माना जा रहा है।

विवाद उस समय शुरू हुआ, जब यह पता चला कि, गत वर्ष ग्वांगी प्रांत के तकरीबन 2490 एलिमेंटरी, मिडिल व हाई स्कूलों की लाइब्रेरी से जो 2528 किताबें हटाई गई थीं, उनमें कांग की किताब “द वैजिटेरियन” भी शामिल थी। हटाई गई सभी पुस्तकों को छात्रों के लिए हानिकारक माना गया था। इन पुस्तकों में हन कांग की किताब ही नहीं बल्कि, एक और नोबल पुरस्कार विजेता लोक होजे सारागामो की पुस्तक “ब्लाड-डनेस” माइकल रोज़मन की, “यू: द ओनर्स मैनुअल”, जिसे जर्मनी

■ किताब में बच्चों को आरम्भ से ही सैक्स एजुकेशन देने की बात कही गई है, जो सारे विश्व में सराही जा रही है, पर, कोरिया के परम्परावादी खेमों ने इस किताब का सख्त विरोध किया है और इस किताब को उन स्कूलों व पुस्तकालयों में प्रतिबंधित कर दिया है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं।

में “साइंस बुक ऑफ द ईयर” अवॉर्ड मिला था तथा टाइम्स एजुकेशनल सॉल्यूशंस सीनियर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीतने वाली, सूज़न मैरिडिथ की “वॉट्स हैपनिंग टु मी” शामिल है। आखिरी दो किताबें, किशोरों के लिए सैक्स एजुकेशन तथा मानव शरीर के बारे में हैं।

यह कदम तब उठाया गया, जब ग्वांगी प्रोविंशियल ऑफिस ऑफ एजुकेशन एक रूढ़िवादी एन.जी.ओ. को सलाह पर स्कूलों को पुस्तकों के बारे में मैनो भेजा। एन.जी.ओ. ने स्कूलों को सैक्स संबंधी किताबें हटाने की सलाह दी थी। तथापि, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्पोर्ट्स एण्ड टूरिज्म के तहत आने वाली पब्लिकेशन इण्डस्ट्री प्रमोशन एजेंसी

ऑफ कोरिया ने हटाई गई किताबों में से केवल एक किताब को युवाओं के लिए हानिकारक माना।

हान की, लिटरेचर में नोबल की ऐतिहासिक जीत के बारे में स्कूलों और घरों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई।

दो बेटियों की माँ, ली ने कहा, “मेरी बेटों, जो आठवीं कक्षा में हैं, ने कहा कि वो हान की किताब “द वैजिटेरियन” पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके टीचर्स ने उसे “ह्यूमन एक्ट्स” नाम की दूसरी किताब पढ़ने की सलाह दी। ली ने आगे कहा, “द वैजिटेरियन” को मेरी बेटों की उम्र के बच्चों के लिए अनुपयुक्त बताया गया।

माताओं के एक लाइन कैफे में एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुशांत डैथ केस में रिया चक्रवर्ती को राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर सर्वोच्च न्यायालय ने इस सप्ताह के शुरु में सी.बी.आई. तथा महाराष्ट्र की उस अपील को “सारहीन” बताते हुये खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती तथा भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ जारी किये गये “लुक आउट सर्कुलर्स” (एल.ओ.सी.) को रद्द कर दिया गया था।

रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती तथा उनके पिता लेफ्टिनेन्ट कर्नल इन्द्रजीत चक्रवर्ती को “लुक आउट सर्कुलर” सी.बी.आई. द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच के सिलसिले में जारी किये गये थे।

■ सुप्रीम कोर्ट ने सी.बी.आई. द्वारा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक और पिता रिटायर्ड सैन्य अधिकारी इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ जारी “लुक आउट सर्कुलर” को रद्द कर दिया।

एल.ओ.सी. को रद्द कर देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सी.बी.आई. की याचिका को “सारहीन” बताते हुये, न्यायमूर्ति वी.आर. गवई तथा के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जाँच एजेंसी इस शीर्ष अदालत में केवल इसलिये आई है, क्योंकि आरोपी हाई प्रोफाइल वाले लोग हैं।

इसके बाद, बेंच ने सी.बी.आई. की याचिका खारिज कर दी। सी.बी.आई. ने इनके खिलाफ एल.ओ.सी. उस समय जारी किये थे, जब राजपूत के परिवार ने पटना में एक एफ.आई.आर. दर्ज करके, राजपूत की मृत्यु की जाँच की माँग की थी। उच्च न्यायालय ने ये एल.ओ.सी. फरवरी 2024 में रद्द कर दिये थे तथा कहा था कि सी.बी.आई., एल.ओ.सी. जारी करने के कारण नहीं बता पाई है।

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसरों की वकालत करने वाली प्रमुख आवाजों में से एक भौतिक विज्ञानी रोहिणी गोडबोले का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 72 वर्ष की थीं।

पद्म श्री से सम्मानित गोडबोले 25 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में उच्च ऊर्जा भौतिकी केन्द्र से जुड़ी रहीं। उन्होंने 2018

■ प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया।

में सेवानिवृत्ति के बाद मानद प्रोफेसर के रूप में काम किया है। पुणे में जन्मी गोडबोले एसपी कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), बॉम्बे की पूर्व छात्रा थीं। बारह नवंबर 1952 को जन्मी गोडबोले ने 1979 में अमेरिका के स्टोनी ब्रुक विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया।

प्रधानमंत्री ने गोडबोले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने शोक संदेश में कहा, रोहिणी गोडबोले जी के निधन से बहुत दुःख हुआ। वह एक अग्रणी वैज्ञानिक और नवोन्मेषक थीं, जो विज्ञान की दुनिया में अधिक महिलाओं की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अक्टूबर। प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें केन्द्र सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नेशनल कानून बनाने और लागू करने का आग्रह किया है। हालांकि इसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने इस पर असंतोष जताया है। ज्ञातव्य है कि प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया (पी.सी.आई.) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद ने किया है। पत्रकारों की गिरफ्तारी, गैर कानूनी तरीके से बन्दी बनाने और धमकाने के

खिलाफ यह प्रस्ताव पी.सी.आई. सदस्य गुरबीर सिंह ने बनाया था, जिसे 27 सितम्बर को बहुमत से स्वीकार किया गया था। इसमें प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया एक्ट को ज्यादा शक्तियाँ देने की मांग की गई है, ताकि यह लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए उपर रही चुनौतियों व खतरों से निपटने में सक्षम हो सके। सिंह लिखते हैं कि अभी पी.सी.आई. सिर्फ सलाहकारी आदेश ही दे सकती है, जो बाध्यकारी नहीं होता है, इसलिए उन तत्वों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में मांग की गई है कि पुलिस के लोगों को लोकतंत्र

■ प्रेस काउन्सिल की मीटिंग में पत्रकार गुरबीर सिंह ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकारें काउन्सिल के आदेश को उपदेश मात्र मानकर उपेक्षित कर देती हैं तथा आदेश की परवाह नहीं करती हैं और पत्रकारों को धमकाती हैं।

■ प्रस्ताव में बताया गया है कि वर्ष 2023 में भारत में 5 पत्रकारों की हत्या हुई तथा 226 पत्रकारों को सरकारों, राजनेताओं ने और असाामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया।

के चौथे स्तम्भ के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उनके साथ आचरण के नियम बनाए जाएं। उदाहरण के लिए, एक पत्रकार की

सिंह ने कहा कि उच्चस्तर से लेकर निम्नस्तर के कॉस्टेबल तक, सभी के लिए गंभीर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाए और उन्हें पत्रकारों के साथ सम्मान से व्यवहार करना सिखाया जाए। रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में देश भर में पत्रकारों की हत्या हुई है तथा 226 को राज्य सरकारों ने या असाामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया है। सिंह ने कहा कि प्राइवेट सर्वे के अनुसार भारतीय समाचार संघ गंभीर दबाव में काम कर रहे हैं। प्रेस फ्रीडम की जहाँ तक बात है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 2024 में भारत का स्थान 180 देशों में 159 वां है।

प्रस्ताव में पत्रकारों से जुड़े कई मामलों का जिक्र है, जिनमें समाचार पोर्टल न्यूजक्लिक पर दिल्ली पुलिस की रेड भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को न्यूजक्लिक के 86 पत्रकारों पर रेड की थी। न्यूजक्लिक पोर्टल के संस्थापक संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन चीफ अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के दंगों को कवर कर रहे कारवां मैगजीन के पत्रकार पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट पर पी.सी.आई. (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हमारी सरकार ने किसानों का दुख-दर्द समझा है-भजनलाल

खींवर में भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा की नामांकन सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया

खींवर, 25 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के दुःख-दर्द को समझती है तथा किसानों से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर काम कर रही है। हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि से लेकर गेहूँ की एम.एस.पी. तक में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में अब सरकार भूँग की एम.एस.पी. पर खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए



मुख्यमंत्री भजनलाल ने शुक्रवार को खींवर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित किया तथा भाजपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया।

उन्होंने जनसभा में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मात्र 10 महीने में 50 प्रतिशत वादे पूरे किये हैं। आगे भी एक-एक वादे को पूरा किया जायेगा।

नामांकन सभा में केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राज्य के मंत्री गजेन्द्र खींवर, झाबर सिंह खर्रा, सुरेश रावत, के.के. बिश्नोई, जोगेश्वर गर्ग, मंजू बाधमार, किसान आयोग के अध्यक्ष बी.आर. चौधरी, विधायक व पदाधिकारी उपस्थित थे।

पेयजल एवं सिंचाई में पानी की महत्ता को समझते हुए हमने सरकार में आते ही ई.आर.सी.पी. और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों की विरोधी है, क्योंकि इनके नेताओं ने तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यमुना जल समझौते को निरस्त करने का वादा किया था।

शर्मा शुक्रवार को खींवर में विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी रेवंतराम डांगा के समर्थन में आयोजित नामांकन सभा को संबोधित

कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लूट और झूठ की पार्टी है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किये गये किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, जबकि हमने मात्र 10 महीने में ही संकल्प पत्र में किए गए 50 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं तथा आगे भी एक-एक वादे को पूरा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपरलीक मामलों से पहले साल में ही हम एक लाख नौकरी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागौर राजस्थान की हृदयस्थली है। यहां के जवान-किसान मजबूती से काम करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम किसानों को सुचारू रूप से पर्याप्त बिजली देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख 24 हजार करोड़ के एम.ओ.यू. किए हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से रेवंत राम डांगा को भारी मतों से जिताकर

विधानसभा भेजने की अपील की। इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवर, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, उद्योग राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाधमार, किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी सहित, विधायक, वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

‘घर का जोगी...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
पोस्ट में लिखा था, “हान कांग की ‘वैजिटेरियन’ मेरे बच्चे की स्कूल लाइब्रेरी में ‘टू बाय’ (खरीदने) लिस्ट में है। हमारे बच्चे संभोग के ऐसे कामोत्तेजक वर्णन वाली किताब कैसे पढ़ सकते हैं?”

पोस्ट लिखने वाली ने कहा कि वो स्कूल को इस संबंध में औपचारिक शिकायत करेगी। तथापि, कुछ लोगों का कहना है कि अपने बच्चों को विश्वभर में मान्यता प्राप्त किताब को पढ़ने से रोकना बेतुकी बात है। सिओल के एक हाई स्कूल के एक टीचर ने “द कोरिया हेरल्ड” को बताया “हमें गर्व होना चाहिए कि इस वर्ष का लिटरेचर का नोबल पुरस्कार दक्षिण कोरिया की लेखक को मिला है। वे साहित्य में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली इस क्षेत्र की पहली महिला हैं।”

विख्यात ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
वकालत करती थी। उनके शैक्षणिक प्रयास आने वाली पीढ़ी यों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”

एडिशनल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आदेश पवन कुमार की जमानत याचिका पर दिया। अधिवक्ता रविन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत को बताया गया था कि उसने परिवारी पक्ष को राजीनामे के तौर पर 34 लाख रुपये एडिशनल एस.पी. सुरेश खींची की मौजूदगी में दिए थे, जबकि वे मामले में आई.ओ. भी नहीं थे। जिस पर अदालत ने एडिशनल एस.पी. खींची को उपस्थित होकर उनकी भूमिका बताने के लिए कहा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। उनकी जगह एस.आई. संतराम ने पेश होकर कहा कि खींची मेघालय में प्रशिक्षण हेतु व्यस्त है। इसके साथ ही डी.जी.पी. ऑफिस से जारी एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि एफ.आई.आर. गंगपुर सिटी पुलिस थाने की है और उस समय खींची का परिवारी पक्ष से परिचय था।

उनकी ओर से व्यक्तिगत हैसियत से मध्यस्थता की गई है और पदीय अधिकारों का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। दरअसल परिवारी स्कूल संचालक ने 2022 में आरोपी स्कूल लेखाकार पर रुपए गबन करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जून 2024 में गिरफ्तार कर लिया और वह तब से जेल में ही है। आरोपी का कहना था कि एडिशनल एस.पी. खींची के प्रभाव के चलते यह अनुचित कार्रवाई की गई और उससे जबरन राजीनामा करवाया गया, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

‘विभागीय कार्यवाही ...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता 6 नवंबर से पहले भारत लौट आएंगे और तत्काल इसकी जानकारी विभाग को देगा। इसके अलावा, वह सिंगपुर को छोड़कर किसी अन्य देश की यात्रा नहीं करेगा। याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड में अधिकारी है। उसने अपने सिंगपुर रहने वाले अपने बेटे से मिलने के लिए 26 सितंबर को प्रार्थना पत्र पेश कर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, लेकिन विभाग ने उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामला हाईकोर्ट में आने के बाद, अदालत ने विभाग को नोटिस जारी किए। उसकी विभाग को तामील होने के बाद, उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए और अदालत को जानकारी दी कि विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसे विदेश में रह रहे बेटे से मिलने का मौलिक अधिकार है। इसलिए उसे विदेश जाने की मंजूरी दी जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को सशर्त विदेश जाने की अनुमति दी है।

प्रेस काउन्सिल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने असंतोष जताया तथा फ्रांस की न्यूज एजेंसी द्वारा तैयार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की सत्यता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “रैंकिंग की पद्धति संदिग्ध है तथा पी.सी.आई. ने पहले भी इन रिपोर्ट्स की प्रामाणिकता पर संदेह जताया था।” देसाई ने कहा कि इंडियन प्रेस फ्रीडम एनुअल रिपोर्ट, जिसे इंडियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनिशिएटिव ने बनाया, की प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र चुनाव में हरियाणा के चुनाव नतीजों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिव सेना को धीरे-धीरे दक्कनार करती जा रही है, क्योंकि उसका मानना है कि केन्द्र सरकार तथा भाजपा नेतृत्व के समर्थन और सहारे के बावजूद शिंदे, उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में असफल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस, जिसने 2019 में केवल एक सीट जीती थी, ने इस बार काफी आगे बढ़ते हुए, 13 सीटें जीती थीं।

टिकट-वितरण तथा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर भाजपा नेता देवेन्द्र फडनवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच चल रहा तनाव पहले ही सामने आ चुका है। भाजपा और

आर.एस.एस. यह सुनिश्चित करने के लिये अथक प्रयास कर रही हैं कि अगर भाजपा इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है, तो वह मुख्यमंत्री पद के लिये अपना प्रत्याशी आगे ला सकती है। लेकिन ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती कि भाजपा अपने बल पर सरकार बना लेगी। चुनावों के बाद, शिंदे तथा पवार दोनों का ही भविष्य चुनाव-परिणामों पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र में, भाजपा तथा शिंदे गुट ने चुनाव दो माह विलम्ब से कराने की इच्छा जाहिर की थी, ताकि “लाइली बहना योजना” को क्रियान्वित किया जा सके, लेकिन महायुति गठबंधन इसका पूरा लाभ लेने में विफल रहा है।

हरियाणा की सफलता के बाद, भाजपा ने सीट-वितरण संबंधी वार्ताओं में शिंदे और अजित पवार पर बहाने हासिल करने की व्यवस्था कर ली है। महाराष्ट्र में, मराठा आरक्षण भाजपा के लिये बड़ी महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। मनोज जरांगे पाटिल इस आंदोलन के नेता के रूप में उभरे हैं तथा कई सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिये हैं। ये प्रत्याशी दोनों ही गठबंधनों के वोट काट सकते हैं। पाटिल के समर्थकों का मानना है कि पाटिल भाजपा को हराने के लिये काम कर रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री फडनवीस के कार्यकाल में, उनके आंदोलन को कमजोर करने के प्रयास किये गये थे।

30% TO 50% OFF ON MAKING CHARGES FOR PLAIN GOLD JEWELLERY

40% OFF ON MAKING CHARGES FOR TEMPLE & ANTIQUE JEWELLERY

30% OFF ON MAKING CHARGES FOR PREMIUM GOLD JEWELLERY

FLAT 25% OFF ON MAKING CHARGES FOR EVERY PURCHASES BELOW 30 GRAMS

KALYAN SPECIAL 1g GOLD RATE ₹7295 SAVE ₹215 PER GRAM MARKET 1g GOLD RATE ₹7510****

UP TO ₹5000 CASHBACK USING HDFC BANK CREDIT CARDS

HDFC BANK FESTIVE TREATS

2% CASHBACK ON HDFC BANK CREDIT CARDS MIN TRANSACTION: ₹75,000 VALIDITY: 19th - 31st OCT 2024

**JAIPUR: AJMER ROAD - CRM NO.: 73405 61233 | VAISHALI NAGAR - CRM NO.: 91158 03333 | UDAIPUR - CRM NO.: 88756 78133
JODHPUR - CRM NO.: 94133 12103 | KOTA - PH: 91459 50033 | BIKANER - PH: 80033 93933**

OPEN ON ALL DAYS

FOR MORE DETAILS CONTACT US ON TOLL FREE NUMBER: 1800 425 7333 | WWW.KALYANJEWELLERS.NET | FOLLOW US ON @KALYANJEWELLERS

BIKAJI

बनाए रिश्ते खास, बीकाजी गिफ्ट हेम्पर के साथ

25% OFF ON MAKING CHARGES FOR EVERY PURCHASES BELOW 30 GRAMS

Regional Sales Manager: Pankaj Mittal, M: 9838572233, Area Sales Manager: Vipin Awasthi, M: 9414209211, Anoop Singh, M: 9810697713 Sales Officer: Aayush Pareek, M: 9782238086, Sunil Kumawat, M: 9829668928, Mukesh Pareek, M: 9414407768, Vishal Singh Panwar, M: 9414954268, Kunal Kalra, M: 7976906519, Omprakash Thathera, M: 9314135013, Soun Singh, M: 9314964590

Bikaji Exclusive Showroom: SK Marketing, M: 9314508605 • Dev Marketing, M: 9829022711 • Bikaner Bhujia & Namkeen, M: 9414060435 • Raj Shree Resort, Chandwaja (Jaipur) 7229846444

Authorised Distributors: • Frontier Distributors (Hindaun City) M: 9828560192 • Ishu Sales Agencies (Karauli) M: 9414726175 • Gaurav Enterprises (Sapotra) M: 9509091111

www.bikaji.com • Download 'Bikaji Online' App from Google play | App Store | Follow us on: f | i | t

BHUJIA • NAMKEEN • SWEETS • PAPAD • SNACKS

38F/BK/52-24